दौरान हुए निर्यात से कम था । 1998-99 के दौरान (अक्तूबर, 1998 तक) हुए निर्यात पर प्रोदभूत कुल आए पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई 11.36 करोड़ रू0 की आय की तुलना में 4.14 करोड़ रू0 थी ।

कोयला खानों की रायल्टी का पुन: निर्धारण

319. **श्री रामजीलाल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कोयला खदानों की रायल्टी के पुनर्निधारण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने कोककर कोयले और "ए", "बी" और "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की आधार कीमतों के 25 प्रतिशत और "डी", "ई" "एफ" और "जी" ग्रेड अकोककर कोयले की कीमतों के 20 प्रतिशत तक कोयले की रायल्टी दरों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया है । पिछले वर्षो में आयातित कोयलेकी तुलना में भारतीय कोयले की उत्पादन लागत कम है, फिर भी उच्च भाड़ा-शुल्क और उच्च रॉयल्टी लेवी के कारण देश में भारतीय कोयले की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समाप्त हो गयी है । इस परिप्रेक्ष्य में रायल्टी की दरों में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया जाएगा ।

Amendment lo Coai Mines (Nationalisation) Act, 1973

320. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government propose to move amendments to the Coal Mines (Nationalisation) Act. 1973 in the direction of privatisation of coal mines;

(b) if so, whether Government held discussions with the Trade Unions which are against Government's move;

(c) it so, the details thereof; and

(d) if not, tbe reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) The Ministry of Coal propose the make amendment to Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 to allow coal mining by Indian companies without existing restriction of captive consumption. The proposal does not involve privatisation of any of the existing coal mines of Coal India Limited (CIL) or of Singareni Collieries Company Limited (SCCL).

(b) and (c) The proposal was discussed wirti the Trade Unions on several occasions. While the unions recognised that a demand supply gap will remain at the end of the IX Plan, they insisted that increased production by the nationalised coal companies should be made possible by increasing budgetary support to them. It was explained to them that provision of budgetary support to CIL has been stopped since 1995-96 and it is not possible to restore the support.

(d) Does not arise in view of the answer given to paras (b) and (c) of the Question.

कोयले पर रायल्टी

320. **श्री नरेश यादव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्यों की ओर से कोयले पर रायल्टी के रूप में देयताओं की अदायगी करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने इन अनुरोधों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) सरकार को विद्यमान दरों के अनुसार कोयले पर रायॅल्टी के रूप में देय बकाया राशि का भुगतान किए जाने के लिए राज्य सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । राज्य सरकारों की ओर देय रायॅल्टी की राशि की वसूली कोयला कंपनियों द्वारा